Date
17/04/2020

विषय - समकालीन भारत और शिक्षा
प्रकरण - कोठारी कमीशन

B Ed Ist Year
Period - Ist

आयोग का मूल्यांकन

आयोग के गुण :- (1) आयोग ने देश के समक्ष शिक्षा की एक उत्तम और व्यापक योजना प्रस्तुत की।

(2) सामान्य स्कूलो की स्थापना के विषय मे सुझाव देकर देश मे समानता और समाजवाद का बिगुल बजाया है।

(3) अध्यापक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए उपयोगी सुझाव दिये।

(4) शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए पंचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव उत्तम।

(5) त्रिभाषा सूत्र संशोधन द्वारा भारत की उलझी हुई भाषा समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त सुझाव दिये।

(6) कार्यानुभव एवं वैज्ञानिक शिक्षा की उन्नति के सुझाव दिये।

(7) आयोग ने पाठ्यक्रम परिवर्तन करने, परीक्षा पद्धति सुधारने एवं चयनित प्रवेश के उत्तम सुझाव दिये।

(8) तकनीकी, व्यवसायिक, कृषि शिक्षा सम्बन्धी भी आयोग के सुझाव उचित एवं सराहनीय है।

17-04-2020 10:39

आयोग के दोष

(1) जी० एन० आचार्य ने लिखा "आयोग का प्रतिवेदन बेसिक शिक्षा की मृत्यु का अनुमति पत्र है।"

(2) आयोग के सुझावों को लागू करने के लिए विशाल धनराशी की आवश्यकता थी।

(3) त्रिभाषा - सूत्र संशोधन में अंग्रेजी को भारत में अनिश्चित काल तक बनाये रखने की सिफारिश करके कोई उपयुक्त सुझाव नहीं दिया।

(4) शिक्षक - प्रशिक्षण सम्बन्धी आयोग के सुझाव महत्वपूर्ण होते हुए भी अस्पष्ट और अनिश्चित हैं।

(5) आयोग के अनेक सुझाव या तो अत्यन्त सामान्य प्रकृति के हैं या अत्यन्त आदर्शवादी हैं।

(6) स्त्री शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा विषयक सुझाव पूर्व आयोगों व समितियों के सुझावों की पुनरावृत्ति ही हैं।

(7) प्राथमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में दिये गये आयोग के सुझाव भी यथार्थ से अत्यधिक दूर और साधनों के अपव्यय को बढ़ाने वाले हैं।

17-04-2020 10:39

भारत की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के विकास में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की भूमिका

आयोग की कमियों के बाद भी यह स्वीकार करना होगा कि स्वतन्त्रता - प्राप्ति के पश्चात भारत की आधुनिक शिक्षा के विकास के क्षेत्र में कोठारी आयोग का प्रतिवेदन अत्यन्त व्यापक, उपयोगी, स्पष्ट, सृजनात्मक, उत्तम और ऐतिहासिक है।

कार्यान्वयन के कुछ प्रमुख बिन्दु हैं)

(1) शिक्षा आयोग की सुस्तुतियों और विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं तथा संगठनों के सुझावों पर विचार कर 1968 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का एक प्रस्ताव तैयार किया गया।

(2) पाँचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में शिक्षा की नयी संरचना 10+2+3 को प्रारम्भ किया गया।

(3) मा० शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजनाएँ बनाकर उन्हें राज्य सरकारों को दिया गया।

(4) विद्यार्थियों की उनके कार्य एवं क्षमता के अनुसार साधारण तथा उन्नत, दो स्तर पर कुछ विषयों में पाठ्यक्रम चयन की अनुमति दी गई।

(5) नई संरचना 10+2+3 के अन्तर्गत कार्य-अनुभव को शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाया गया।

(6) बुक बैंकों की स्थापना की गई।

(7) राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई।

(8) शिक्षकों के वेतनमान संशोधित कर उनकी सेवा-शर्तों में सुधार किया गया।

Complete

Sidhi Tyagi
17/04/2020

17-04-2020 10:39